

केयर्न एनर्जी और भारत सरकार - रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स और मध्यस्थता कार्यवाही

केयर्न एनर्जी पीएलसी: एक परिचय

केयर्न यूरोप की प्रमुख स्वतंत्र तेल और गैस अन्वेषण और विकास कंपनियों में से एक है।

स्थापित होने के बाद तीन से अधिक दशकों में, केयर्न ने एक ऑपरेटर और भागीदार दोनों ही रूप में दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में तेल और गैस की खोज, विकास और उत्पादन गतिविधियाँ सफलतापूर्वक की हैं।

केयर्न की खोज गतिविधियाँ वर्तमान में भौगोलिक दृष्टि से उत्तर पश्चिम यूरोप, पश्चिम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में केंद्रित हैं, जो ब्रिटेन के उत्तरी सागर में उत्पादन और विकास परिसंपत्तियों के हितों से जुड़ा हुआ है। पूर्व में इसका ध्यान दक्षिण एशिया पर भी रहा।

जहां भी यह संचालित होता है, केयर्न का उद्देश्य सभी हितधारकों के लाभ के लिए अपनी संपत्ति और लोगों में मूल्य की खोज, विकास और वितरण करना है।

केयर्न लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर 30 से अधिक वर्षों से सूचीबद्ध है और इसके पास एक अंतर्राष्ट्रीय ब्लू-चिप शेयरहोल्डर बेस है। इसके प्रमुख निवेशकों में एबरडीन स्टैंडर्ड, अवीवा, लीगल एंड जनरल, श्रोडर्स, ब्लैकरॉक, एमएफएस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कोलंबिया थ्रेडनिडल और फिडेलिटी इंटरनेशनल शामिल हैं। इसके लगभग 60% निवेशक यूके में, 30% अमेरिका में और बाकी यूरोप और शेष विश्व में हैं।

इंटरनेशनल ब्लू-चिप शेयरहोल्डर्स में निम्न शामिल हैं:



भारत में केयर्न

केयर्न एनर्जी ने पहली बार 1990 के दशक में भारत में निवेश किया था जब यह देश के तेल और गैस उद्योग में भाग लेने वाली शुरूआती अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में से एक बन गई थी। भारत में केयर्न के निवेश ने कंपनी को रावा तेल और गैस क्षेत्र को रूपांतरित करते हुए देखा। जब केयर्न ने 1990 के दशक के मध्य में यहाँ ऑपरेटर का जिम्मा संभाला तब ये क्षेत्र प्रतिदिन 3,000 बैरल तेल का उत्पादन कर रहा था। सिर्फ 18 महीनों के भीतर, केयर्न ने उत्पादन को 50,000 बैरल ऑयल प्रतिदिन तक बढ़ा दिया। रावा अभी भी, दो दशक से अधिक समय से, उत्पादन में है और इसने 36.5 करोड़ बैरल तेल समतुल्य उत्पादन किया है जो मूल अनुमानों से काफी अधिक है। जबकि उत्पादन के अब चौथे दशक में विस्तार की उम्मीद है।

इसके बाद केयर्न ने जनवरी 2004 में राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र की खोज के साथ भारत के तेल और गैस उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन खोजों में से एक थी। इसके बाद भाग्यम और ऐश्वर्या तेल खोजों के साथ तेजी से इसका अनुसरण किया गया। आज मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्षेत्र में कुल मिलाकर लगभग 2.2 बिलियन बैरल का तेल भंडार मौजूद है।

केयर्न ने अंततः इस क्षेत्र में चालीस से अधिक खोज की और, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, कंपनी ने लगभग 45000 करोड़ रूपए (US \$ 6 बिलियन) परियोजनाओं में निवेश किया, जिसने भारत, इसके तेल और गैस उद्योग और स्थानीय समुदायों को लाभान्वित किया है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से भारत के पश्चिमी तट तक कच्चे तेल को ले जाने के लिए दुनिया की सबसे लंबी गर्म पाइपलाइन (c.600 किमी) का निर्माण था। एक दशक बाद, टर्मिनल अभी भी भारत के पूरे कच्चे तेल के उत्पादन का एक तिहाई से अधिक प्रदान करता है।

इन फ़ील्ड्स का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ा है। हजारों कुशल नौकरियों का निर्माण करने के साथ-साथ, उन्होंने कृषि, वस्त्र और पर्यटन जैसे अन्य क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित किया है, जिसका अर्थ है कि राजस्थान का बाड़मेर जिला (मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्षेत्रों के लिए) अब ऐसी औसत आय का दावा करता है राष्ट्रीय औसत की तुलना में 40% अधिक है और राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। पिछले एक दशक में, केयर्न की खोजों ने राज्य और राष्ट्रीय सरकार के लिए 1.5 लाख करोड़ (US\$ 20 बिलियन) से अधिक का राजस्व उत्पन्न किया है।

केयर्न का 2006 में पुनर्गठन और आईपीओ

2006 की शुरुआत में, केयर्न ने अपने भारत के कारोबार को अलग करने और तेल क्षेत्रों के विकास के लिए पूंजी जुटाने के उद्देश्य से एक अलग इकाई के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए एक घरेलू भारतीय तेल और गैस व्यवसाय बनाने के साथ-साथ यूके मूल कंपनी के शेयरधारकों को कुछ मूल्य वापस प्रदान करने की पहल की। केयर्न चाहती तो नए व्यवसाय को हांगकांग, सिंगापुर या लंदन सहित विभिन्न स्थानों में सूचीबद्ध किया जा सकता था, लेकिन भारतीय निवेशकों को कंपनी की सफलता में हिस्सेदारी करने का अवसर देने के लिए भारत को चुना और इसे उपलब्ध सर्वोत्तम भारतीय प्रबंधन प्रतिभा को आकर्षित करने में सक्षम बनाया।

आईपीओ की तैयारी के लिए, केयर्न ने कर अधिकार क्षेत्र के लिए भारत में अधिवासित सहायक केयर्न इंडिया लिमिटेड (CIL) बनाने के लिए समूह का पुनर्गठन किया। उत्पादन शुरू होने से तीन साल पहले CIL के लिए कर योग्य राजस्व से काफी पहले ही भारतीय अधिकारियों को पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करते हुए यह संरचनात्मक परिवर्तन हुआ।

केयर्न ने सभी विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया और भारत के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, जिसमें भारतीय राजस्व सचिव, और वित्त मंत्रालय, दोनों शामिल हैं, से सभी आवश्यक अनुमोदन की मांग की। दोनों ने पूरी तरह से लेन-देन संरचना को मंजूरी दी। भारत के इतिहास में सबसे बड़े आईपीओ को ले जाने के लिए, केयर्न ने बीस से अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों को नियुक्त किया, जो पूरी तरह से कुछ महीनों की प्रक्रिया में लगे हुए थे। केयर्न ने कई अलग-अलग दलों से विशिष्ट सलाह प्राप्त की, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पुनर्गठन के संबंध में भारत में कोई कर देय नहीं था।

केयर्न इंडिया को जनवरी 2007 की शुरुआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था जिसने भारत में निवेशकों को सफल लिस्टिंग में भाग लेने का अवसर दिया। कंपनी ने राजस्थान में तेल संसाधनों के विकास के अंतिम चरण में मदद की।

मंगला फ़ील्ड पर 2009 में उत्पादन शुरू हुआ जब मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल भी बनाया गया और केवल 18 महीनों में पूरा किया गया। 2004 में मंगला क्षेत्र की खोज से लेकर 2009 में पहला तेल उत्पादन तक, केयर्न ने इस परियोजना को केवल पाँच वर्षों में 'खोज से विकास तक' पूर्ण किया। राजस्थान के कच्चे तेल को बाजार में ले जाने के लिए, केयर्न ने दुनिया की सबसे लंबी गर्म पाइपलाइन के निर्माण के लिए ~ 7500 करोड़ रूपए (US\$ 1 बिलियन) का निवेश किया। चरम निर्माण में, टर्मिनल पर 11,000 और पाइपलाइन पर 5,000 के साथ लगभग 16,000 कर्मचारी कार्यरत थे। राजस्थान का विकास थार रेगिस्तान के केंद्र में भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस परियोजनाओं में से एक था।

अगले दशक में केयर्न एनर्जी ने केयर्न इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेची, जो मुख्य रूप से 2009 में पेट्रोनैस और 2011 में वेदांता को मिली।

चूंकि इन ट्रांसफर्स में भारतीय कंपनी (CIL) के शेयर शामिल थे, वे भारतीय कर अधिनियमों के दायरे में आते थे। तदनुसार, केयर्न ने आवश्यक कर मंजूरी के लिए आवेदन किया और 2009 और 2011 में भारतीय पूंजीगत लाभ कर में 3700 करोड़ रूपए (US \$ 500 मिलियन) से अधिक का भुगतान किया। उन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप, भारतीय कर अधिकारियों ने 2006 के समान लेनदेन की कई मौकों पर जांच की। किसी भी बिंदु पर कोई सुझाव नहीं दिया गया था कि 2006 के लेनदेन में कर योग्य हस्तांतरण शामिल थे।

2012 का रेट्रोस्पेक्टिव कानून

रेट्रोस्पेक्टिव (पूर्वव्यापी) कर अधिनियम का मुद्दा पहली बार लोगों के ध्यान में आया जब राजस्व विभाग ने वोडाफोन के खिलाफ एक "परीक्षण मामले" के रूप में वर्णित एक गैर-भारतीय कंपनी में शेयरों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण में टैक्स की मांग की थी। जनवरी 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से इस मामले को वोडाफोन के पक्ष में पाया, उन्होंने ये पुष्टि की थी कि ऐसे हस्तांतरण भारतीय कर दायरे में नहीं थे।

16 मार्च 2012 को, सुप्रीम कोर्ट ने कर विभाग का विस्तार करने के आयकर विभाग के प्रयासों को सर्वसम्मति से खारिज करने के दो महीने से कम समय बाद, वित्त मंत्रालय ने वित्त विधेयक 2012 में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 9(1)(i) में रेट्रोस्पेक्टिव संशोधन पेश किया। अन्य बातों के अलावा, यह समझाया कि एक गैर-भारतीय कंपनी के शेयरों को हमेशा भारत में स्थित माना जाएगा, अगर इसका मूल्य अंतर्निहित भारतीय परिसंपत्तियों से पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है। वोडाफोन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसे "स्पष्ट" बताया हुआ, वित्त अधिनियम 2012 ने घोषणा की

कि पूर्वव्यापी संशोधन को 50 साल पहले यानी 1 अप्रैल 1962 से लागू होने के बाद माना जाएगा। कानून के मुख्य वास्तुकार तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने स्वयं बाद में लिखा था कि कानून का उद्देश्य "वोडाफोन कर मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन करना था।"

आईपीओ समूह पुनर्गठन के आठ साल बाद जनवरी 2014 में, केयर्न एनर्जी सीआईएल में अपनी अंतिम हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही थी। उसी समय भारतीय आयकर विभाग ने कंपनी में एक रेट्रोस्पेक्टिव कर जांच शुरू करने का फैसला किया।

इसके परिणामस्वरूप, केयर्न को भारत आयकर विभाग (IITD) से यह सूचना मिली कि उसे केयर्न इंडिया लिमिटेड (CIL, जिसे अब VL में मिला दिया गया है) में अपने शेष ~10% शेयर को बेचने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। आईआईटीडी ने बाद में इस शेयरहोल्डिंग के अधिकांश हिस्से को बेच दिया और आय और लाभांश भुगतान प्राप्त किया। अधिसूचना में, आईआईटीडी ने आईपीओ की तैयारी में 2006 में किए गए इंटर-ग्रुप शेयर ट्रांसफर से उत्पन्न अघोषित कर योग्य आय की पहचान करने का दावा किया। अधिसूचना ने 2012 में बनाए गए रेट्रोस्पेक्टिव भारतीय कर कानून का संदर्भ दिया, जिसे आईआईटीडी 2006 के लेनदेन पर लागू करना चाहता था।

इसका प्रभाव

यह घटनाक्रम भारत में 20 साल के निवेश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण निष्कर्ष है जहां केयर्न ने एक आदर्श कॉर्पोरेट नागरिक का व्यवहार किया और एक एक ऐसी विरासत संपत्ति बनाई है जिसे साझेदारी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

इसका केयर्न के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय शेयरधारकों के लिए एक प्रमुख हानिकारक प्रभाव पड़ा। केयर्न को संपत्ति बेचना पड़ा, प्रमुख निवेशों को स्थगित करना पड़ा और अपने कार्यबल में पर्याप्त कमी करना पड़ा। इसके अलावा कार्रवाई ने कई वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश के जोखिम पर संशय और सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है।

वर्तमान स्थिति

केयर्न ने मार्च 2015 में यूके-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की। आर्बिट्रेशन (संधि विवाद समाधान की सहमति विधि) यह निर्धारित करेगी कि क्या भारत द्वारा 2006 में किए गए आंतरिक कॉर्पोरेट पुनर्गठन के लिए एक नए अधिनियमित पूंजीगत लाभ कर कानून को लागू कर भारत में केयर्न के निवेशों की रक्षा के लिए संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया गया है। केयर्न का मानना है कि नव अधिनियमित कानून का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग उस संधि के तहत भारत के अपने दायित्वों का उल्लंघन है जिसके तहत इसे और इसके निवेशों को निष्पक्ष और समान रूप से देखा जाना चाहिए था और केयर्न के निवेश को गैरकानूनी रूप से प्राप्त करने से बचना चाहिए था।

आर्बिट्रेशन पैनल में डॉ लॉरेंट लेवी (अध्यक्ष), डॉ स्टामिनर अलेक्जेंड्रोव और जे क्रिस्टोफर थॉमस क्यूसी शामिल हैं। दिसंबर 2018 में पेरिस में अंतिम सुनवाई के पूर्व द हेग में मेरिट सुनवाई 20-31 अगस्त 2018 को हुई थी। संधि के तहत केयर्न के दावे के संबंध में अवॉर्ड की ड्राफ्टिंग जारी है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 22 दिसंबर 2020 को अवॉर्ड जारी किया है।

केयर्न की क्या मांग है?

केयर्न घाटे के लिए पूर्ण पुनर्स्थापन की मांग कर रहा है जो निम्न कारणों से हुआ: 2014 में भारत में इसके निवेश की समाप्ति; रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स उपायों को लागू करने के लिए निरंतर प्रयास; और कंपनी और उसके निवेशों के साथ उचित और समान रूप से व्यवहार करने में विफलता। केयर्न विशेष, दंडात्मक या परिणामी नुकसान के किसी भी रूप के लिए दावा नहीं कर रहा है; एकमात्र नुकसान जो केयर्न की मांग है, सीआईएल में ग्रुप के अवशिष्ट शेयरहोल्डिंग के मूल्य के बराबर है जो आईआईटीडी ने जब्त कर लिया था और बाद में इसे बेच दिया था (आय को बरकरार रखते हुए), और इसके अलावा एक असंबंधित मामले में केयर्न के कारण आगे की वापसी जिसे IITD द्वारा भी जब्त किया गया था, जिसकी कीमत लगभग INR 10570 करोड़ (US \$ 1.4 बिलियन) थी।

केयर्न के पास कानूनी सलाह है जो यह पुष्टि करती है कि आईआईटीडी द्वारा केयर्न से अंततः प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम राशि सीयूएचएल की परिसंपत्तियों के मूल्य तक सीमित है, मुख्य रूप से वीएल में सामान्य और वरीयता के शेयर, जिनमें से लगभग सभी पहले ही बेच दिए गए हैं और / या भुनाए गए हैं, साथ ही 2009 और 2011 से जब्त लाभांश और कर रिफंड इसमें शामिल हैं।

विस्तृत कानूनी सलाह के आधार पर, केयर्न अपनी कानूनी स्थिति के बारे में आश्वस्त है। तदनुसार, IITD द्वारा मूल्यांकन किए गए किसी भी कर या दंड के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। संधि एक सफल पुरस्कार को लागू करने के लिए मजबूत

प्रावधानों की पुष्टि करती है और ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है। केयर्न इस नतीजे को स्वीकार करेंगे।